

व्यूज ब्रीफ

जुबीन गर्ग मामले में मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज
दिसपुर। असम के चर्चित जुबीन गर्ग मौत मामले में मुख्य आरोपी श्यामकुनु महता को गौहाटी हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि आरोपी के फरार होने और सबूतों से छेड़छाड़ करने का जोखिम है। जस्टिस मिताली ठाकुरिया की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले 30 अप्रैल को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट भी महता की जमानत याचिका खारिज कर चुकी थी।

दिल्ली हाईकोर्ट में अभिजीत दीपके की याचिका पर सुनवाई
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कोकोरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके की याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कोरव ने खाते को सुरत बहाल करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले के दूरगामी परिणाम होने के कारण वह सरकार की बात सुनने के बाद ही कोई कदम उठाएगा। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।

लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का टिन शेड गिरा
लखनऊ। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-5 का टिन शेड गिर गया। इसमें एक टीटीई और 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टीटीई का नाम भूपेंद्र है। वहीं, यात्री अभिषेक और साहिल घायल हैं। आरपीएफ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। घायल तीनों यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुणे में जहरीली शराब पीने से 13 की मौत
पुणे। पुणे में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 8 मौतें पिंपरी चिंचवड इलाके में हुई हैं, कई की हालत गंभीर है। पिंपरी-चिंचवड के दापोडी और फुगेवाडी क्षेत्रों में 8 और पुणे के काले पाडल और हडपसर इलाकों में 5 लोगों की मौत हुई है।

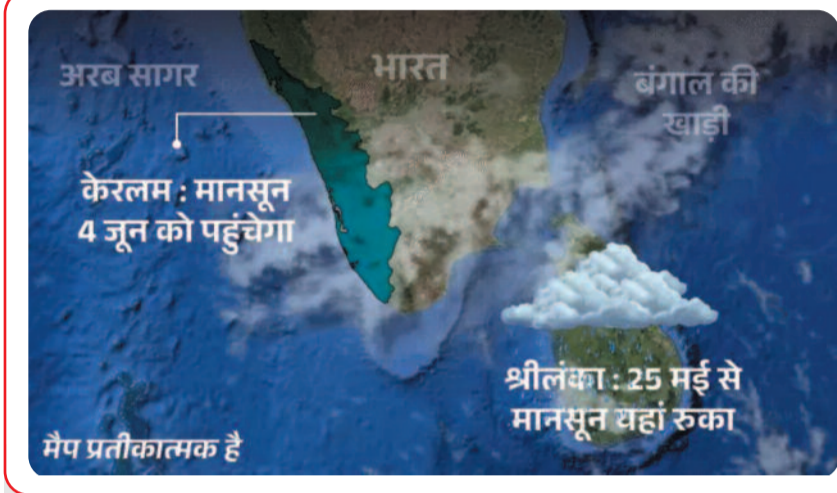
राष्ट्रबाण
अगर आपको नहीं मिल रहा है आपका लोकप्रिय अखबार राष्ट्रबाण तो आज ही अपने हॉकर से बोलिए या हमें कॉल कीजिए
सिर्फ 100 रुपए महीना
संपर्क : 7000427433

तूफानी हवाओं ने श्रीलंका में रोका; 10% कम बारिश का अनुमान, जून-जुलाई में भी हीटवेव चलेगी

R नई दिल्ली | एजेंसी
राष्ट्रबाण rashtrabaan.in
देश में मानसून की एंटी लेट हो गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि श्रीलंका के ऊपर कम दबाव वाली तूफानी हवाओं के चलते मानसून केरलम तट से 30-35 किमी दूर 5 दिन से अटका है और अगले 2-3 दिन इसके आगे बढ़ने के आसार नहीं हैं। केरलम के तट पर मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 1 जून मानी जाती है। इससे पहले मौसम विभाग ने 26 मई तक ही मानसून आने का अनुमान जताया था। ताजा अनुमान के मुताबिक अब यह 7 दिन बाद केरल तट पर पहुंचेगा। यानी, पिछले अनुमान से मानसून करीब 10 दिन बाद देश में एंटी करेगा।
आईएमडी के मुताबिक जून-जुलाई में भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश में हीटवेव चलने की संभावना है। आमतौर पर उस वक्त तापमान 30-35 डिग्री तक रहता है। इस बार 3 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर रहेगा।
इस साल बारिश भी 10% तक कम होगी

मौसम विभाग ने बताया कि इस साल देश में औसतन 78 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान है।

मानसून अब 7 दिन बाद केरलम पहुंचेगा



कोर जोन में कम बारिश से खेती पर सीधा असर
मौसम विभाग ने बताया कि इस साल मानसून के कोर जोन में कम बारिश होगी। इस इलाके में खेती सबसे ज्यादा मानसूनी बारिश पर निर्भर करती है। यानी बारिश का सीधा असर फसलों और खाद्य उत्पादन पर पड़ता है। मानसून कोर जोन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का विदर्भ, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, कुछ हिस्से उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके आते हैं। यहां खेती पर असर पड़ने से किसानों को सीधा नुकसान होगा।

कमजोर मानसून, कम बारिश का आम आदमी पर असर...
देश में कुल बारिश का करीब 75% हिस्सा मानसून के दौरान होता है, जो सिंचाई, पीने के पानी और बिजली उत्पादन के लिए श्रेष्ठ जरूरी है। करीब 64% आबादी कृषि पर निर्भर है। सिर्फ 55% खेती योग्य जमीन ही सिंचाई से कवर है। कम बारिश का असर खरीफ सीजन की बुवाई, फसल उत्पादन और कुल कृषि गतिविधियों पर पड़ेगा, जिससे किसानों की लागत और जोखिम दोनों बढ़ सकते हैं। बारिश कम होने से उत्पादन घट सकता है, जिसका असर सप्लाई पर पड़ेगा और इससे सब्जियों, दालों सहित खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। खेती कमजोर रहने पर गांवों में आय कम हो सकती है, जिससे ग्रामीण बाजार में खर्च और मांग दोनों प्रभावित होंगे। ग्रामीण मांग में कमी आने पर ट्रेक्टर और ट्रैक्टर जैसे वाहनों की बिक्री पर भी असर पड़ने की संभावना है। अगर बारिश कम रहती है तो डैम और जलाशयों का जलस्तर सामान्य से नीचे रह सकता है, जिससे आगे चलकर पानी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। कम बारिश और ज्यादा गर्मी की स्थिति में बिजली की खपत बढ़ेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां तापमान ज्यादा रहता है।

जो सामान्य से करीब 10% कम है। 13 अप्रैल को 80 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान लगाया गया था। 1971-2020 के आंकड़ों के आधार पर देश में औसत बारिश 87 सेंटीमीटर मानी जाती है। जून में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में कम बारिश मौसम विभाग ने बताया कि



बिहार में भारी बारिश, 20 जिलों में दिन में अंधेरा
बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत; यूपी में 100किमी का तूफान
नई दिल्ली | एजेंसी
राष्ट्रबाण rashtrabaan.in
बिहार में शुक्रवार को आंधी और बारिश का अलट जारी किया है। पटना, खगड़िया, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, छपरा समेत 20 जिलों में सुबह पहले अंधेरा छा गया फिर तेज बारिश हुई। राज्य में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। काले बादलों की वजह से गाड़ियों की लाइट जलाकर लोग सफर करते देखे गए। मौसम विभाग के मुताबिक, बिहार में अगले 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। उधर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, सूरना, श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश हुई। 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलतीं।

यूपी में निर्माणधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 की मौत
हमीरपुर। यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणधीन पुल का स्लैब शुक्रवार देर रात 2 बजे गिर गया। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीआरएफ) ने मलबे में फंसे 3 मजदूरों को निकाला। साढ़े 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। उत्तर प्रदेश बिज कॉर्पोरेशन के एमडी धर्मवीर सिंह ने दैनिक भास्कर को बताया कि आंधी-बारिश के कारण स्लैब गिरा और नीचे सो रहे मजदूर दब गए।

राहुल ने दिल्ली में ऑटो ड्राइवर्स के साथ खाना खाया, पार्क में जमीन पर बैठे
नई दिल्ली | एजेंसी
राष्ट्रबाण rashtrabaan.in
लोकसभामें विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली के बंगाली मार्केट में बने टोडरमल पार्क में ऑटोरिक्षा ड्राइवर्स के बीच पहुंचे। जहां उन्होंने ऑटोचालकों से बात की। राहुल उनका यूनिफॉर्म पहने भी नजर आए। पार्क में बैठे राहुल के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वे ऑटो ड्राइवर्स के साथ खाना खाते

कर्नाटक में 4 डिप्टी सीएम हो सकते हैं : डीके शिवकुमार सीएम होंगे, शपथ अगले हफ्ते संभव

R बेंगलुरु | एजेंसी
राष्ट्रबाण rashtrabaan.in
कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही सिद्धारमैया शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरेगे से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बैठक में सिद्धारमैया ने हाईकमान के सामने अपनी कई मांगें रखीं, जिनमें बेटे यतींद्र सिद्धारमैया के लिए नए मंत्रिमंडल में अहम मंत्रालय की मांग भी शामिल बताई जा रही है।
उधर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर

कर लिया गया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक पार्टी सूत्रों ने कहा है कि डीके अगले हफ्ते नए मंत्रियों के साथ शपथ ले सकते हैं। सरकार में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए 4 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं।
मीटिंग के बाद बोले डीके-अभी कुछ तय नहीं हुआ है:
कांग्रेस शिवकुमार ने को कहा कि राज्य में नई कैबिनेट बनाने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। सब कुछ हाईकमान के कहने के मुताबिक हो रहा है। शनिवार को कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की एक मीटिंग बुलाई गई है। पार्टी के सभी विधायकों से मीटिंग के लिए बेंगलुरु में मौजूद रहने को कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- जमानत पर आदेश उसी दिन या अगले दिन दें, अपलोड तुरंत करें हाईकोर्ट 3 महीने से ज्यादा फैसला सुरक्षित न रखें

R नई दिल्ली | एजेंसी
राष्ट्रबाण rashtrabaan.in
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सभी हाईकोर्ट में फैसलों में देरी पर चिंता जताई है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, 'किसी भी मामले में फैसला सुरक्षित (रिजर्व) रखने के बाद उसे 3 महीने के भीतर सुनाया जाना चाहिए। अगर 3 महीने तक फैसला नहीं आता है, तो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल उस मामले को चीफ जस्टिस के सामने रखेंगे।'
सीजेआई सूर्यकांत की अग्रुआई वाली बेंच ने यह भी कहा कि जमानत याचिकाओं पर आदेश उसी दिन सुनाया जाए। अगर

कोर्ट ने 4 साल से पेंडिंग केस के मामले में आदेश दिया
यह मामला अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 4 दोषियों की याचिका से जुड़ा है। उनका कहना था कि झारखंड हाईकोर्ट में उनकी क्रिमिनल अपील 2022 से पेंडिंग है, लेकिन अब तक फैसला नहीं सुनाया गया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि फैसले में इतनी देरी संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के

अधिकार का उल्लंघन है। इसमें समय पर सुनवाई और न्याय पाने का अधिकार भी शामिल है। इससे पहले नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी। इसमें यह बताने को कहा गया था कि किन मामलों में फैसला कब रिजर्व रखा गया, कब सुनाया गया और आदेश वेबसाइट पर कब अपलोड किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को 12 निर्देश दिए
निजी स्वतंत्रता से जुड़े मामले, जिनमें रेगुलर बेल, अग्रिम जमानत के सामने शामिल हैं, उनमें हाईकोर्ट

को तेजी दिखानी चाहिए। जमानत याचिकाओं की सुनवाई कर आदेश उसी दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। यदि ऑर्डर रिजर्व रखा जाता है, तो उसे आगले दिन सुनाया जाए। जमानत, सजा पर रोक के आदेश की सूचना जेल प्रशासन को तुरंत भेजी जाए, ताकि आरोपी/दोषी को उसी दिन या अगले दिन रिहा किया जा सके, बशर्ते वह किसी दूसरे केस में वॉन्टेड न हो। या जमानत की शर्तों का पालन न रह गया हो। अगर मामला अपराधिक केस, फांसी की सजा से जुड़ा है, और आरोपी जेल में है तो जज फैसला सुरक्षित रखने के 7 दिन के अंदर दोनों पक्षों से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

न्यूयॉर्क मेयर ममदानी ने ईरान जंग का विरोध किया : कहा- हजारों जान गई

R तेल अवीव | एजेंसी
राष्ट्रबाण rashtrabaan.in
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने ईरान जंग का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह युद्ध अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ममदानी ने कहा, आज से तीन महीने पहले एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ था, जिसके लिए किसी ने वोट नहीं किया था। लेकिन इसकी कीमत उन लोगों ने चुकाई, जिनकी इस्में कोई आवाज नहीं थी।
उन्होंने कहा कि इस युद्ध में हजारों नागरिकों की जान जा चुकी है। साथ ही 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए, जो अब कभी अपने परिवारों के पास वापस नहीं लौट पाएंगे। ममदानी ने कहा कि इस युद्ध का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका के आम लोगों पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और खाने-

ईरान बोला- अमेरिका से समझौते का ड्राफ्ट अभी फाइनल नहीं
ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ समझौते का ड्राफ्ट अभी फाइनल नहीं हुआ है। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक हाल के दिनों में ड्राफ्ट में बदलाव किए गए हैं। एजेंसी को ईरानी अधिकारियों ने बताया कि दोनों देशों के बीच सौजन्यपूर्ण और आसान कार्रवाई सही नहीं है। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में अमेरिका और ईरान

ईरान बोला- अमेरिका से समझौते का ड्राफ्ट अभी फाइनल नहीं
ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ समझौते का ड्राफ्ट अभी फाइनल नहीं हुआ है। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक हाल के दिनों में ड्राफ्ट में बदलाव किए गए हैं। एजेंसी को ईरानी अधिकारियों ने बताया कि दोनों देशों के बीच सौजन्यपूर्ण और आसान कार्रवाई सही नहीं है। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में अमेरिका और ईरान

60 दिन के सीजफायर को बढ़ाने और युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए बातचीत शुरू करने पर शुरुआती सहमति बना चुके हैं। हालांकि इस समझौते को अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मंजूरी मिलना बाकी है। वहीं एक्सप्रैस की रिपोर्ट में कहा गया था कि संभावित समझौते के तहत होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बिना रोकटोक जारी रहेगी और अमेरिकी सैनिकों की बंदरगाहों पर लगी अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा।
बढ़ाने और युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए बातचीत शुरू करने पर शुरुआती सहमति बना चुके हैं। हालांकि इस समझौते को अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मंजूरी मिलना बाकी है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- जमानत पर आदेश उसी दिन या अगले दिन दें, अपलोड तुरंत करें

कोर्ट ने 4 साल से पेंडिंग केस के मामले में आदेश दिया
यह मामला अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 4 दोषियों की याचिका से जुड़ा है। उनका कहना था कि झारखंड हाईकोर्ट में उनकी क्रिमिनल अपील 2022 से पेंडिंग है, लेकिन अब तक फैसला नहीं सुनाया गया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि फैसले में इतनी देरी संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के

अधिकार का उल्लंघन है। इसमें समय पर सुनवाई और न्याय पाने का अधिकार भी शामिल है। इससे पहले नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी। इसमें यह बताने को कहा गया था कि किन मामलों में फैसला कब रिजर्व रखा गया, कब सुनाया गया और आदेश वेबसाइट पर कब अपलोड किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को 12 निर्देश दिए
निजी स्वतंत्रता से जुड़े मामले, जिनमें रेगुलर बेल, अग्रिम जमानत के सामने शामिल हैं, उनमें हाईकोर्ट

को तेजी दिखानी चाहिए। जमानत याचिकाओं की सुनवाई कर आदेश उसी दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। यदि ऑर्डर रिजर्व रखा जाता है, तो उसे आगले दिन सुनाया जाए। जमानत, सजा पर रोक के आदेश की सूचना जेल प्रशासन को तुरंत भेजी जाए, ताकि आरोपी/दोषी को उसी दिन या अगले दिन रिहा किया जा सके, बशर्ते वह किसी दूसरे केस में वॉन्टेड न हो। या जमानत की शर्तों का पालन न रह गया हो। अगर मामला अपराधिक केस, फांसी की सजा से जुड़ा है, और आरोपी जेल में है तो जज फैसला सुरक्षित रखने के 7 दिन के अंदर दोनों पक्षों से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।



पिछले कुछ समय में पूरी दुनिया में योग के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। वर्तमान समय में, लोग अपनी कई छोटी-बड़ी शारीरिक व मानसिक समस्याओं के लिए दवाइयों के स्थान पर योग का सहारा लेने लगे हैं। जिसके कारण अब इस क्षेत्र में कॅरियर की नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। अगर आप भी खुद को फिट रखने के साथ-साथ दूसरों को भी हेल्दी बनाना चाहते हैं और अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो बतौर योगा टीचर अपना भविष्य देख सकते हैं-

स्किल्स

एक कुशल योगा टीचर बनने के लिए आपके कम्युनिकेशनल व इंटरपर्सनल स्किल्स बेहतर होने चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके भीतर दृढ़ इच्छाशक्ति, व दूसरों को मोटिवेट करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको योग के किसी एक पैटर्न जैसे आध्यात्मिक योग, योगा थेरेपी, बच्चों के लिए योग, वृद्धों के लिए योग आदि में स्पेशलाइजेशन करके अपने कार्य को शुरू कर सकते हैं।

क्या होता है काम

एक योगा टीचर का काम महज लोगों को योग

नई संभावनाएं पैदा कर रहा है योग

करवाना ही नहीं होता, बल्कि उन्हें अपने क्लाइंट्स की शारीरिक व मानसिक परेशानी को समझते हुए उनके अनुरूप योग करवाना होता है। इसके अतिरिक्त वह अपने क्लाइंट के अनुसार सेशन को प्लान करना होता है। इतना ही नहीं, एक योगा टीचर अपनी कक्षा को मजेदार बनाने के लिए हर दिन कुछ अलग-अलग योगासनों का अभ्यास करवाए।

योग्यता

इस क्षेत्र में कॅरियर देख रहे छात्र ग्रेजुएशन के बाद डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। आजकल विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के आधार पर भी योग का प्रशिक्षण दिया जाता है।

बनी रहती है। इसके अतिरिक्त आप किसी बड़े सेलिब्रिटी के पर्सनल योगा टीचर बनकर अच्छी ख़ासी कमाई कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो खुद का योग स्कूल भी खोल सकते हैं।

आमदनी

योगा टीचर की आमदनी उसकी योग्यता, अनुभव व प्रसिद्धि के आधार पर तय होती है। जैसे-जैसे आपका इस क्षेत्र में अनुभव बढ़ता जाता है और लोग आपके काम को सराहने लगते हैं तो



प्रमुख संस्थान

- मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग, दिल्ली।
- देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड।
- गुरुकुल कॉंगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड।
- डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
- अमरावती विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र।
- मुम्बई विश्वविद्यालय, एमजी.रोड, फोर्ट, मुम्बई।
- देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर।
- अख्यंगर योग सेंटर, पुणे।
- बिहार स्कूल ऑफ योगा, मुंगेर।
- स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु।

संभावनाएं

एक कुशल योगा टीचर की डिमांड हमेशा बनी रहती है। आप विभिन्न योग केन्द्र से लेकर स्वास्थ्य केन्द्रों में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में फ्रीलांस काम किया जा सकता है। वैसे एक योगा टीचर या योगा थेरेपिस्ट की मांग स्कूल, हेल्थ रिसेंट, अस्पताल, जिम, हाइसिंग सोसाइटियों, व टेलीविजन स्वास्थ्य चैनल्स पर भी

पेंटिंग एक बेहतरीन कॅरियर है और एक पेंटर आर्ट गैलरीज से लेकर न्यूजपेपर, मैगजीन, पोस्टर, फिल्म व टीवी इंडस्ट्री में आर्टवर्क की तलाश कर सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हैं या फिर किसी फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट व कॉलेज में बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। अगर चाहें तो खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलें।



अपने शौक को बना लें अपना कॅरियर

बचपन में हम सभी ने अपने हाथों में ब्रश उठाकर पेंटिंग की है। पेंटिंग करना यकीनन हर किसी के मन को सुकून देता है, लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, वह शौक कहीं पीछे छूटने लगता है। काम की आवाधापी में ब्रश हाथों से कब दूर चला जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर आपको पेंटिंग करना बेहद पसंद है तो क्यों न अपने इसी शौक को आप अपना कॅरियर बना लें। तो चलिए जानते हैं इस क्षेत्र के बारे में-

क्या होता है काम

एक पेंटर कई तरह के सरफेस पर पेंटिंग करता है। उसका काम डोमेस्टिक से लेकर इंडस्ट्रियल हो सकता है। वह सिर्फ छोटे स्केल पर कागज पर पेंटिंग नहीं करता और न की उसका काम सिर्फ केनवास तक सीमित है, बल्कि वह घर को रिडेकोरेट करने से लेकर ब्रिज या अन्य हैवी व बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी अपना कलात्मकता उकेरता है।

स्किल्स

इस क्षेत्र में सफलता के लिए सबसे जरूरी है आपका कल्पनाशील होना। इसके अलावा आपको पेंट कलर्स, टोन्स, हाइलाइट व आर्ट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। आपको कलर्स के शेड्स व उनकी मिक्सिंग की जानकारी भी होनी चाहिए। कई बार एक पेंटर को कई बड़े प्रोजेक्ट करने होते हैं, इसलिए उसे टीम के साथ भी काम करना होता है। साथ ही आपको कई घंटों तक काम करना पड़ सकता है, इसके लिए आप फिजिकली व मेंटली तैयार रहें। एक पेंटर सिर्फ पेंटिंग ही नहीं करता, बल्कि अपने काम को लोगों के सामने पेश भी करता है, इसलिए आपके कम्युनिकेशन व लैंग्वेज स्किल भी अच्छी होनी जरूरी है।

योग्यता

एक पेंटर बनने के लिए अलग से किसी स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन पेंटिंग की बारीकियों को समझने और अपना हाथ साफ करने के लिए आप इस क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स जैसे बीए इन पेंटिंग, बीए पेंटिंग, स्कलपचर, अक्वाड्रार्ट्स, बीएफए पेंटिंग, कोर्स आदि कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद इस क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया जा सकता है।

संभावनाएं

पेंटिंग एक बेहतरीन कॅरियर है और एक पेंटर आर्ट गैलरीज से लेकर न्यूजपेपर, मैगजीन, पोस्टर, फिल्म व टीवी इंडस्ट्री में आर्टवर्क की तलाश कर सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हैं या फिर किसी फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट व कॉलेज में बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। अगर चाहें तो खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलें।

आमदनी

इस क्षेत्र में आमदनी इस बात पर निर्भर करती है कि आपका काम लोगों को कितना पसंद आता है, लेकिन फिर भी शुरूआती दौर में आप बीस से पच्चीस हजार आसानी से कमा सकते हैं। वहीं कुछ सालों के एक्सपीरियंस व आपके काम की पापुलैरिटी के आधार पर आपकी आमदनी कई गुना बढ़ भी सकती है।

प्रमुख संस्थान

- नाथ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगांव
- एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, जालंधर
- गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स, चंडीगढ़

एक आईसक्रीम टेस्टर का मुख्य काम हर तरह की आईसक्रीम को चखकर उसके टेक्सचर, कलर, स्मेल, अपीयरेंस और अन्य चीजों का आकलन करता है और आईसक्रीम की गुणवत्ता के बारे में विस्तार से बताता है।

आईसक्रीम का नाम सुनते ही हर किसी का मन उसे खाने के लिए मचल जाता है। बच्चे हो या बड़ा, हर किसी की फेवरेट होती है। वैसे तो आपको भी आईसक्रीम बेहद पसंद होगी। अमूमन लोग पैसे खर्च करके आईसक्रीम खरीदते हैं और उसका स्वाद चखते हैं लेकिन अगर आपको फ्री में आईसक्रीम खाने को मिले। इतना ही नहीं, आईसक्रीम चखने के लिए भी आपको पैसे मिलने लगें तो। शायद इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। जी हां, अगर आप आईसक्रीम के दीवाने हैं तो इसे ही अपना कॅरियर बना सकते हैं। आईसक्रीम टेस्टर एक ऐसा ही क्षेत्र है, जिसमें व्यक्ति आईसक्रीम को चखकर उसके स्वाद के बारे में बताता है। तो चलिए जानते हैं इस क्षेत्र के बारे में-

क्या होता है काम

एक आईसक्रीम टेस्टर का मुख्य काम हर तरह की आईसक्रीम को चखकर उसके टेक्सचर, कलर, स्मेल, अपीयरेंस और अन्य चीजों का आकलन करता है और आईसक्रीम की गुणवत्ता के बारे में विस्तार से बताता है। हालांकि इस क्षेत्र में आपका काम अनुभव के साथ बढ़ता जाता है। एक टेस्टर सिर्फ आईसक्रीम को चखता ही नहीं है, बल्कि अपने टेस्ट बड के आधार पर टीम को नए फ्लेवर की आईसक्रीम को इनवेंट करने में भी मदद करता है। कई बार वह आईसक्रीम या कंपनी के लिए विपणन प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है।

स्किल्स - इस क्षेत्र में आपकी सफलता की कुंजी है आपका टेस्ट बड। इस क्षेत्र में आपका टेस्ट बड अच्छा होने के साथ उसकी कल्पनाशीलता भी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप नए-नए टेस्ट के फ्लेवर को इन्वेंट करने में मदद कर सकें। इतना ही नहीं, आपमें धैर्य भी होना चाहिए क्योंकि कई बार एक आईसक्रीम टेस्ट को दिन



आईसक्रीम को बना सकते हैं अपना कॅरियर

होना बेहद जरूरी है। यह क्षेत्र उतना ही आसान नहीं है, जितना देखने में लगता है। दिन में कई तरह की आईसक्रीम खाने के बाद व्यक्ति का दूध बढ़ता है या तबियत खराब होती है और लगातार आईसक्रीम खाने से कुछ लोगों को आईसक्रीम से ही नफरत हो जाती है और इससे उसका टेस्टबड भी खराब हो जाता है।

योग्यता - इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए अलग से आईसक्रीम टेस्टर का कोर्स फिलहाल मौजूद नहीं है। लेकिन आप 12वीं के बाद फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए आप किसी फूड टेस्टिंग सर्वे या कॉम्पटीशन में भाग ले सकते हैं। साथ ही किसी बड़ी आईसक्रीम कंपनी में इंटरशिप करके खुद को इस फील्ड के लिए तैयार कर सकते हैं। संभावनाएं - अगर बात इस क्षेत्र में स्कोप की बात हो तो आज सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी एक प्रोफेशनल आईसक्रीम टेस्टर की डिमांड है। कई प्रतिष्ठित आईसक्रीम बनाने वाली कंपनियां व उभरती कई कंपनियों में आपके लिए काम की कमी नहीं है। वैसे आजकल कई होटल्स व फूड चेन भी खुद को स्थापित करने के लिए अपनी खुद की आईसक्रीम बनाती हैं। आप वहां पर भी काम तलाश कर सकते हैं। आमदनी - एक आईसक्रीम टेस्टर शुरूआती दौर में 30000 से 50000 रूपए प्रतिमाह आसानी से कमा सकता है। वैसे अगर आपका टेस्ट बड आपका साथ देता है तो आपकी आमदनी प्रतिमाह लाखों में हो सकती है। वैसे सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में प्रोफेशनल आईसक्रीम टेस्टर की काफी डिमांड है। वहां पर सैलरी पैकेज काफी आकर्षक होता है।



पॉलिटेक्निक करने के बाद इन क्षेत्रों में नौकरी का सुनहरा अवसर

पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रोग्राम एक फुल टैक्निकल डिग्री कोर्स है जो ऑल इंडिया काउंसिल फोर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा संचालित है। इन पाठ्यक्रमों को विशेष रूप से छात्रों को संबंधित स्ट्रीम या विषय के प्रैक्टिकल पहलुओं और बेसिक बातें सीखने में मदद करने के लिए चलाया जाता है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एक टेक्निकल डिग्री है जो आपको एक अच्छी नौकरी दिलाने में मदद कर सकती है। केवल नौकरी ही नहीं बल्कि इस कोर्स के अन्य लाभ भी हैं। आइए विस्तार से इन लाभों और पॉलिटेक्निक के बाद करियर के विषय में जानते हैं।

बी.टेक लेटरल एंट्री स्कीम

पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने वाले छात्रों के लिए इंजीनियरिंग डोमेन से सबसे लोकप्रिय विकल्प बीटेक या बीई है। लेटरल एंट्री का मतलब है कि आप बीटेक/बीई के दूसरे वर्ष या तीसरे सेमेस्टर में सीधे इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। कई कॉलेज लेटरल एंट्री के लिए अलग से प्रवेश परीक्षा करते हैं।

एएमआईई सर्टिफिकेशन

इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से डिप्लोमा करने वाले छात्रों के लिए एएमआईई सर्टिफिकेशन एक अन्य विकल्प हो सकता है। इयूएन (इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के एसोसिएट सदस्य) सर्टिफिकेट बीई के समकक्ष एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। कोर्स पूरा करने वाले उम्मीदवारों को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, इंडिया द्वारा सम्मानित किया जाता है।

पॉलिटेक्निक कोर्स के बाद करियर

10 वीं कक्षा के छात्रों के लिए, जो फाइनैशियल परेशानियों से जूझ रहे हैं वो छात्र 10वीं कक्षा के बाद पॉलिटेक्निक के जरिए रोमांचक और बेहद आकर्षक करियर अपना सकते हैं। आइए जानते हैं किन क्षेत्रों में छात्र अपना करियर बना सकते हैं।

पब्लिक सेक्टर

पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारकों को सरकार यानी पब्लिक सेक्टर करियर के बेहतरीन अवसर प्रदान करती हैं। ये कंपनियां जूनियर स्तर के पदों (इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग उम्मीदवारों दोनों के लिए) और तकनीशियन स्तर की नौकरियों के लिए डिप्लोमा धारकों को नियुक्त करती हैं।

प्राइवेट सेक्टर

सार्वजनिक क्षेत्रों की तरह ही प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, विशेष रूप से जो मैनुफैक्चरिंग, कस्टमर और इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार डोमेन में काम करती हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारकों को नियुक्त करती हैं। हालांकि, ये नौकरियां जूनियर लेवल की हैं और इनमें प्रमोशन या विस्तार की बहुत कम गुंजाइश है।

सेल्फ एम्प्लॉयमेंट

सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारकों के लिए एक और बेहतर करियर विकल्प है। पॉलिटेक्निक संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले सभी डिप्लोमा कोर्स विशेष रूप से छात्रों को संबंधित विषय के थ्योरी या एप्लीकेशन ओरिएंटेड पहलुओं में ट्रेन करने के लिए तैयार किए गए हैं। यह छात्रों को विषय की मूल बातें सीखने और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए तैयार करता है।



मुनाफे का 'मायाजाल': लाखों की ठगी में घिरे सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष वैभव बिसेन

63 लाख का दांव, 10 लाख लौटाए... बाकी मांगे तो मिली मौत की धमकी!

बालाघाट पुलिस ने दर्ज किया मामला

राष्ट्रबाण संवाददाता
rashtrabaan.in

बालाघाट जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में ज्यादा मुनाफा दिलाने का लालच देकर 63 लाख रुपये की कथित ठगी करने और पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच के बाद ग्राम गरां निवासी दिलीप भैरम और ग्राम पंचायत गरां सरपंच व जिला सरपंच संघ जिलाध्यक्ष वैभव बिसेन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता गंभीर धाराओं के तहत गुरुवार की दोपहर में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता जितेंद्र उर्फ मोनु भगत ग्राम गरां निवासी ने पुलिस अधीक्षक बालाघाट को शिकायत की थी, जिसके पश्चात एसपी ने आदेशानुसार महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपियों ने उसे अधिक मुनाफा कमाने का लालच देकर बड़ी

सरपंच संघ अध्यक्ष वैभव बिसेन के खिलाफ महिला थाना में अपराध दर्ज



दिलीप भैरम आरोपी।



वैभव बिसेन, अध्यक्ष जिला सरपंच संघ (आरोपी)



जितेंद्र उर्फ मोनु भगत पीड़ित।

मामले की जांच महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक किरण वरकड़े द्वारा की गई। जांच के दौरान शिकायतकर्ता, दोनों आरोपियों तथा गवाहों के बयान दर्ज किए गए। साथ ही बैंक खातों का

स्टेटमेंट एवं ब्याजसप चैट के स्क्रीनशॉट भी जांच में शामिल किए गए। जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता मोनु भगत की फर्म एम.एस. रूमी ट्रेडर्स के सेंट्रल बैंक खाते से 6 फरवरी 2025 को 40

लाख रुपये तथा 9 जुलाई 2025 को 20 लाख रुपये आरोपी दिलीप भैरम के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। इसके अतिरिक्त 11 जुलाई 2025 को 3 लाख रुपये दर्ज किए गए। जांच में यह भी सामने

आया कि आरोपियों द्वारा केवल 10 लाख रुपये वापस लौटाए गए, जबकि शेष 53 लाख रुपये वापस नहीं किए गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उसने कई बार पैसे वापस मांगे तो आरोपी सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष वैभव बिसेन ने उसे जान से मारने की धमकी दी, वहीं दिलीप भैरम ने अपने बचाव में शिकायतकर्ता के खिलाफ ही पुलिस और न्यायालय में शिकायत दर्ज करा दी। दूसरी ओर आरोपी दिलीप भैरम ने जांच में दावा किया कि उसने पहले नगद राशि शिकायतकर्ता को दी थी और वहीं रकम बाद में बैंक खाते में वापस ली गई थी। हालांकि वह यह स्पष्ट नहीं कर सका कि इतनी बड़ी नगद राशि उसने कब, क्यों और किसके सामने दी थी। पुलिस जांच में आरोपी के दावों को लेकर संदेह की स्थिति बनी रही।

पुलिस लेन, देन के मामले में गहन जांच कर रही है

पुलिस के अनुसार बैंक ट्रांजेक्शन, गवाहों के बयान, ब्याजसप चैट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए

गए हैं। इसके बाद महिला थाना बालाघाट से प्रतिवेदन भेजे जाने पर कोतवाली पुलिस थाना ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय

न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 351(3) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में

चर्चा का माहौल है। पुलिस अब पूरे वित्तीय लेन-देन, निवेश के दावों और दोनों पक्षों के अन्य दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है।

रकम निवेश करने के लिए प्रेरित किया। शिकायत में बताया गया कि

आरोपी दिलीप भैरम और वैभव बिसेन ने एक राय होकर उससे

कुल 63 लाख रुपये लिए, जिनमें 60 लाख रुपये बैंक खाते के

माध्यम से तथा 3 लाख रुपये नगद दिए गए थे।

लालबर्गा में अस्पताल निर्माण शुरू



अस्पताल के लिए चिन्हित जमीन पर डला लेआउट।

अतिक्रमण और जल निकासी की अनदेखी से भविष्य में गहरा सकता है संकट

राष्ट्रबाण संवाददाता
rashtrabaan.in

बालाघाट जिले के लालबर्गा क्षेत्र के 77 ग्राम पंचायतों और 102 गांवों के ग्रामीणों के लिए एक बड़ी और सुखद खबर है। लालबर्गा में 9 करोड़ 95 लाख रुपये की लागत से 50 बेड के सर्वसुविधा युक्त अस्पताल का निर्माण कार्य निर्माण एजेंसी द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। इसे क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हालांकि, यह अस्पताल अपने निर्माण की शुरुआत से ही सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि इस

अस्पताल का दो बार भूमिपूजन किया गया पहला भूमिपूजन सांसद और विधायक की मौजूदगी में शासकीय तौर पर हुआ, तो वहीं दूसरा भूमिपूजन भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 'कार्यकर्ता सर्वोपरि' के नारे के साथ अलग से किया गया।

विकास के इस बड़े कार्य के बीच अब कुछ गंभीर प्रशासनिक और तकनीकी लापरवाही भी सामने आने लगी है, जो आने वाले समय में बड़ी मुसीबत बन सकती है। स्थानीय नागरिकों और जानकारों का सवाल है कि जिस भूमि पर इतने बड़े अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, क्या उसका विधिवत सीमांकन कराया गया है...? यदि सीमांकन हुआ है, तो फिर अस्पताल की चिन्हित भूमि पर मौजूद पुराने अतिक्रमण को अब तक क्यों नहीं हटाया गया...? बिना अतिक्रमण हटाए अस्पताल

का मूल स्वरूप कैसा होगा और इसका निर्माण सुचारू रूप से कैसे संभव हो पाएगा, यह बड़ा सवाल है।

इसके अलावा, सबसे बड़ी चिंता अस्पताल से निकलने वाले वेस्टेज (बायोमेडिकल वेस्ट) और गंदे पानी की निकासी को लेकर है। वर्तमान में इस गंदगी और पानी की सही ढंग से निकासी कहीं होगी, इस ओर न तो जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया है और न ही प्रशासनिक अधिकारियों ने। यदि समय रहते जल निकासी और अतिक्रमण की समस्या का ठोस समाधान नहीं निकाला गया, तो भविष्य में यह आधुनिक अस्पताल खुद एक बड़ी अव्यवस्था और बीमारी का केंद्र बन सकता है। स्थानीय जनता ने मांग की है कि निर्माण कार्य के साथ-साथ इन बुनियादी समस्याओं का भी तुरंत निराकरण किया जाए।

कम वसूली होने पर होगी कार्यवाही : सीईओ बघेल

शाखा प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों एवं संस्था प्रबंधकों की जिला स्तरीय बैठक सम्पन्न

राष्ट्रबाण संवाददाता
rashtrabaan.in

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट के सभाकक्ष में 28 मई को शाखा प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों एवं संस्था प्रबंधकों की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक मृगाल मीना के मार्गदर्शन में किया गया। बैठक में बैंक के सीईओ अभिनव सिंह बघेल एवं प्रबंधक लेखा पी. जोशी ने बैंकिंग कार्यों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की।

बैठक में ऋण वसूली की वन-टू-वन समीक्षा करते हुए सीईओ श्री बघेल ने निर्देश दिए कि सभी शाखाएं उन्हें आक्टिव लक्ष्य के अनुरूप वसूली कार्य पूर्ण करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गत वर्ष की तुलना में कम वसूली होने पर संबंधित शाखाओं एवं समितियों

के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी, जबकि बेहतर वसूली करने वाली शाखाओं एवं समितियों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। उन्होंने समिति कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे कालातीत एवं अकालातीत कृषकों से घर-घर जाकर संपर्क करें और वसूली कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करें।

बैठक में खरीफ ऋण वितरण, वर्ष 2025-26 के कृषि ऋणों की समीक्षा, शाखा समायोजन, समिति निरीक्षण, पैक्स कम्प्यूटरकरण तथा 'सहकारी से समृद्धि' अभियान की भी समीक्षा की गई। समितियों को अन्य व्यवसायों के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए गए, ताकि उन्हें अतिरिक्त आय के स्रोत प्राप्त हो सकें। श्री बघेल ने बताया कि पैक्स समिति मोरवाही द्वारा इफको मार्ट प्रारंभ किया गया है, जिससे समिति को लाभान्वित प्राप्त हुआ है। इसके अलावा समितियों के पुनर्गठन, मध्यमकालीन ऋण प्रकरण तैयार करने, समिति कर्मचारियों के खातों के संधारण, मत्स्य पालन एवं पशुपालन केंसीसी प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।

ओवरब्रिज की उद्घाटन डेट आगे बढ़ सकती

31 मई से आवाजाही शुरू होनी थी, लेकिन काम अब भी अधूरा; एसडीएम ने किया निरीक्षण



राष्ट्रबाण संवाददाता
rashtrabaan.in

बालाघाट के गरां रेलवे ओवरब्रिज को 31 मई से शुरू करने की योजना फिलहाल टलती नजर आ रही है। काम अभी भी अधूरा है, जिससे देखते हुए अब इसके जून में खुलने के आसार हैं। शुक्रवार को एसडीएम गोपाल सोनी और सेतु सभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पुल का मुआयना किया। ओवरब्रिज के उस हिस्से

प्रशासन ने भी माना-जल्दबाजी ठीक नहीं

हालांकि पहले उम्मीद जताई गई थी कि 31 मई तक पुल शुरू हो जाएगा, लेकिन एसडीएम गोपाल सोनी ने निरीक्षण के बाद साफ किया कि काम पूरा हुए बिना ब्रिज को खोलना संभव नहीं है। अब माना जा रहा है कि जून के पहले या दूसरे हफ्ते तक ही लोग इस पर चल पाएंगे। जैसे ही यह ओवरब्रिज शुरू होगा, बरसों पुरानी रेलवे फाटक हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी।

रेलवे की देरी से अटका काम

यह ओवरब्रिज करीब 750 मीटर लंबा है और इसे बनाने में 21.67 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। राज्य सरकार के हिस्से वाला काम तो दो महीने पहले ही पूरा हो गया था, लेकिन रेलवे की तरफ से काम में देरी होने की वजह से पुल को जनता के लिए खोलने में वकत लग रहा है। ब्रिज शुरू होने से लोगों को बार-बार बंद होने वाले रेलवे फाटक की समस्या से निजात मिल जाएगी।

पर जो रेलवे ने बनाया है, 20 मई को बेरिंग का काम किया गया था। रेलवे इंजीनियरों का कहना है कि इसे ठीक से

सूखने में कम से कम 14 दिन का समय लगता है। इसके अलावा पुल पर अभी चेकर्स टाइल्स लगाने और दीवारों को

बनाने का काम भी बाकी है। इन्ही वजहों से तय समय पर आवाजाही शुरू होना मुश्किल लग रहा है।

आदिवासियों ने गृहमंत्री शाह का पुतला फूँका



'वनवासी' कहे जाने पर जताया विरोध, बोले- हम मूल निवासी

राष्ट्रबाण संवाददाता
rashtrabaan.in

बालाघाट में आदिवासी समाज ने गृहमंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। यह विरोध दिल्ली में एक सम्मेलन के दौरान आदिवासियों को 'वनवासी' कहे जाने पर जताया गया। घटना शुक्रवार शाम 5:30 बजे नगर के काली पुवली चौक पर हुई।

पुतला दहन आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले किया गया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की।

देश के मूल निवासी हैं

आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष दिनेश धुर्वे ने बताया कि 'वनवासी' शब्द के प्रयोग से नाराज होकर यह पुतला दहन किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा, 'हम देश के मूल निवासी हैं, हम आदिवासी हैं, वनवासी नहीं।' धुर्वे ने यह भी कहा कि आदिवासी समाज 'वनवासी' कहे जाने को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा।

जनजातीय पर्यटन की अनूठी मिसाल बना टेकाड़ी

महाराष्ट्र से पहुंचे मेहमानों ने लिया ग्रामीण संस्कृति का आनंद

राष्ट्रबाण संवाददाता
rashtrabaan.in



मेहमानों का पारंपरिक तरीके से पुष्पमाला एवं तिलक लगाकर आत्मीय स्वागत किया गया। ग्रामीण परिवेश, प्राकृतिक सुंदरता और जनजातीय संस्कृति से भरपूर इस आयोजन ने आगंतुकों को विशेष रूप से आकर्षित किया। ग्राम केरा एवं पीपरटोला में स्थापित 08 होम-स्टे में मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था की गई, जिससे स्थानीय होम-स्टे संचालकों एवं ग्राम समितियों को आर्थिक लाभ भी प्राप्त हुआ। अध्ययन भ्रमण के दौरान आगंतुकों को जनजातीय संस्कृति और ग्रामीण जीवनशैली

से रू-ब-रू कराया गया। लोक नृत्य, भजन मंडली, नौका विहार, जंगल ट्रेकिंग, बैलगाड़ी सवारी और स्थानीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मेहमानों का मन मोह लिया। सुबह 5 बजे आयोजित जंगल एवं जलाशय ट्रेकिंग के दौरान आगंतुकों ने प्राकृतिक वातावरण का आनंद लिया तथा सातनारी वॉटरफॉल की मनमोहक छटा को करीब से देखा।

परियोजना के माध्यम से ग्रामीणों को स्वरोजगार और पर्यटन आधारित आजीविका के नए अवसर मिल रहे हैं।

गले में गमछा बंधा, पैरों के पंजे गायब; एसआई ने आत्महत्या की जताई आशंका

बाढ आपदा प्रबंधन को लेकर हुई अधिकारियों की बैठक

राष्ट्रबाण संवाददाता
rashtrabaan.in

वर्षा ऋतु के दौरान अतिवर्षा एवं बड़े जलाशयों से नदियों में पानी छोड़े जाने के कारण बाढ की स्थिति निर्मित होने पर बचाव एवं राहत प्रबंधन के लिए कलेक्टर मृगाल मीना की अंशे यक्षता में 29 मई को अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई और इसमें आवरे यक दिशा निर्देश दिये गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर जीएस धुर्वे, डीपी बर्मन, डिप्टी कलेक्टर प्रदीप कौरव, एसडीएम गोपाल सोनी एवं बाढ आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं जनपद सीईओ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में उपस्थित थे।

राहत शिविर एवं बचाव कार्यों की तैयारी करने के निर्देश



गया। प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर चलाने, राशन एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था करने कहा गया। बाढ की स्थिति में बचाव एवं राहत के लिए होमगार्ड के जवानों की टीम जिले के विभिन्न मुखय स्थलों पर तैनात रखने कहा गया। इसके साथ ही सभी तहसीलों में स्थानीय स्तर पर बचाव एवं राहत के लिए तैराक एवं गोताखोर चिन्हित करने के निर्देश दिये गए। वर्षा ऋतु में पहुंचे विभिन्न ग्रामों के लिए तीन माह के खाद्यान्न का अग्रिम भण्डारण करने के निर्देश दिये गए।

बाढ प्रभावित ग्रामों की जानकारी: बैठक में बताया गया कि चैनगंगा, घिसरी, देवनदी, सोननदी, मानकूर, चंदन, बाघ, महकारी, नदी में बाढ आने से बालाघाट

तहसील के मगरदर्रा, तुमडोटोला, रोशना, टवेझरी, जागपुर, कुहारी, खैरी, बूडी (ढोमटोला), गायखुर्दी, हीरापुर, अमेडा, चिचगांव, भमोडी, गोंगलई, भानपुर, खुटिया, कटंगी, लिंगा, देवरी, हड्डोटोला, छिंदगांव, मंगोलीकला, नेवगांव कला, धडी, भालेवाडा, चरेगांव, घघरिया, बकवाडा, देवसर्रा, सकरी, तीनगडी, नारवाडा, वारासिवनी तहसील के

ग्राम दीनी, पुनी, सिकंदरा, किरनापुर तहसील के ग्राम बटरमारा, खारा, बोडुंदाकला, देवगांव, परसवाडा, कोस्ते, कटंगी, मुर्गी, बवे कर, नीलागांड़ी, बने-हनवाडा, मुण्डेसरा, मुस्कटा, जामडी, डोरिया-परसवाडा, बिनोरा, कडकना, बोरगांव, पले हेरा, अकोला, गुवा, पिपलगांव, पौनी, सर्रा, मौदा, बागडमारा, कोहका, लांजी तहसील के ग्राम टेमनी, कोचेवाही, बडगांव, दुले हापुर, पौसेरा, देवबेली, नेववाही, बेलगांव, देवलागांव, लोडामा, बेहेला, टेमा, अमेडा, मिरिया, टेकेपार, कारंजा, देहांग, कटंगी, रिसेवाडा, अधियाटोला, खैरलांजी तहसील के ग्राम चिचोली, कुहली, मानेगांव, मोवाड, किन्हे ही, टेमनी, सावरी, अतरी, चुटिया, डोंगरिया, गुनुई, घोटी, फुटारा, लावनी एवं लालबर्गा तहसील के ग्राम धरपूर प्रभावित होते हैं।

ढेकेदार की लापरवाही का दंश झेल रहे अमोली और वार्ड नंबर 20 के रहवासी

महज 600 मीटर सड़क और पुलिया निर्माण में महीनों बीते, कछुआ गति से कार्य होने के कारण लोग परेशान, बारिश में रास्ते बंद होने की आशंका

राष्ट्रबाण संवाददाता
rashtrabaan.in

जिले के लालबरी बस स्टैंड से महज 600 मीटर की दूरी पर लालबरी अमोली-समनापुर मार्ग का निर्माण कार्य आम जनता के लिए जी का जंजाल बन गया है। निर्माण एजेंसी और संबंधित ठेकेदार की घोर लापरवाही एवं कछुआ गति से चल रहे कार्य के कारण लालबरी के वार्डवासियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत अमोली के वार्ड नंबर 20 के वाशियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार द्वारा बिना किसी ठोस कार्ययोजना के पुलिया, नाली और सड़क का निर्माण कार्य एक साथ शुरू कर देने से पूरे क्षेत्र में अव्यवस्था का माहौल है और लोगों की मुसीबतें दोगुनी हो गई हैं।



राष्ट्रबाण ने दी मार्ग बंद करने की चेतावनी: वार्ड नंबर 20 अमोली के वार्डवासियों का कहना है कि 'इस

डायवर्जन के कारण अंदरूनी गलियों की सड़कें हुई दयनीय

वार्डवासियों की पुरजोर मांग पर अमोली-समनापुर मार्ग पर 'कलवर्ट बॉक्स पुलिया' का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था। नियमानुसार ठेकेदार को सबसे पहले पुलिया का निर्माण कर आवागमन बहाल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पुलिया निर्माण अधूरा होने के कारण वाहनों के आवागमन को वार्ड नंबर 20 की अंदरूनी गलियों की तरफ डायवर्ट कर दिया गया है। इसके चलते दिन-रात भारी वाहन इन संकरे गलियों से होकर गुजर रहे हैं, जिससे इस मार्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय और जर्जर हो चुकी है।



अंदरूनी मार्ग की मरम्मत हर साल राहवासी आपस में जनसहयोग (चंदा करके करते हैं। अगर इसी तरह भारी

वाहनों का दबाव बना रहा, तो आगामी बारिश में इस सड़क से पैदल चलना भी

दुभर हो जाएगा। ठेकेदार और प्रशासन के अड़ियल रवैये से नाराज वार्डवासियों ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि यदि शीघ्र ही मुख्य मार्ग की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई, तो वे अपने वार्ड की सुरक्षा और सड़क को बचाने के लिए वार्ड नंबर 20 से भारी वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ठेकेदार को निर्देशित कर जल्द से जल्द पुलिया और सड़क का निर्माण कार्य पूरा कराया जाए। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार लालबरी अमोली समनापुर सीसी सड़क का निर्माण कार्य लालबरी के एक स्थानीय जनप्रतिनिधि ने पेटी पर किया है।

पेंच नेशनल पार्क को मिलेगा बायो स्फीयर रिजर्व का दर्जा

यूनेस्को भेजेंगे प्रस्ताव; कान्हा-बांधवगढ़ के साथ मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान; जैव विविधता संरक्षण मजबूत होगा

राष्ट्रबाण संवाददाता
rashtrabaan.in

सिवनी जिले के प्रसिद्ध पेंच टाइगर रिजर्व को जल्द ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'बायोस्फीयर रिजर्व' का विशेष दर्जा प्राप्त हो सकता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की हालिया बैठक में पेंच, कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के 'मेन एंड बायोस्फीयर (इस्को)' कार्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से तैयार प्रस्ताव शीघ्र ही केंद्र के माध्यम से यूनेस्को को भेजा जाएगा।



1179 वर्ग किमी में फैली समृद्ध जैव विविधता



पेंच टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल (कोर और बफर मिलाकर) लगभग 1179 वर्ग किलोमीटर है। एफको द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार, यह क्षेत्र दुर्लभ वनस्पतियों, वन्यजीवों और प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिलने से पेंच को न केवल वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरणीय अध्ययन के लिए अंतरराष्ट्रीय बजट व संसाधनों का लाभ भी प्राप्त होगा।

तीन स्तरों पर होगा पर्यावरण का संरक्षण

बायोस्फीयर रिजर्व के तहत क्षेत्र को कोर और बफर जोन में विभाजित कर संरक्षण को और अधिक कड़ा किया जाएगा। कोर एरिया में मानवीय गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी, जबकि

बफर क्षेत्र में नियंत्रित और टिकाऊ विकास कार्यों को अनुमति दी जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर पुनीत गोयल ने बताया कि इस दर्जे के मिलने से दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा बेहतर होगी और क्षेत्र में इको-टूरिज्म के साथ-साथ संरक्षण की नई राहें खुलेंगी।

स्थानीय रोजगार और संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा

डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने का सीधा लाभ स्थानीय समुदाय को मिलेगा। इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित

होंगे और स्थानीय निवासियों की पारंपरिक जीवनशैली व संस्कृति को वैश्विक मंच पर संरक्षण प्राप्त होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बायोस्फीयर रिजर्व घोषित होने के बाद पेंच दुनिया भर के पर्यावरण प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा।

पेंच की प्रोफाइल:

कुल क्षेत्रफल: 1179 वर्ग किलोमीटर।
वर्तमान दर्जा: टाइगर रिजर्व।
प्रस्तावित दर्जा: यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व।

ईएसएस प्रोफाइल को समग्र आईडी एवं आधार से लिंक कराने के निर्देश

सिवनी। प्रभारी कलेक्टर अनिल कुमार राठौर द्वारा जिले के समस्त आहरण एवं संचितरण अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि आईएसएसआईएस अंतर्गत शासकीय सेवकों के ई.एस.एस. प्रोफाइल का समग्र आईडी से सत्यापन एवं आधार से लिंक/मैपिंग का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए।

राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर जोर



प्रभारी कलेक्टर अनिल कुमार राठौर ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिशे

लोक सेवा केंद्रों

उन्होंने लोक सेवा केंद्रों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि नागरिक सेवाओं से जुड़े प्रकरणों का निराकरण तय समय सीमा में होना चाहिए। सभी अधिकारी प्रतिदिन लंबित आवेदनों की समीक्षा कर समय-सीमा का विशेष ध्यान रखें ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

प्राकृतिक आपदा राहत

प्राकृतिक आपदा राहत प्रकरणों की समीक्षा के दौरान प्रभारी कलेक्टर ने प्रभावित परिवारों को शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्यवाही अत्यंत आवश्यक है।

सीएम हेल्पलाइन

सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का नियमानुसार निराकरण कर उन्हें संतुष्टिपूर्वक बंद कराया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निराकरण में

निर्देश दिए। उन्होंने स्वामित्व योजना के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण एवं नागरिकों को स्वामित्व अधिकार उपलब्ध कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण योजना है। अतः सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में किया जाए। फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा के दौरान प्रभारी कलेक्टर ने शेष किसानों के पंजीयन की कार्यवाही युद्धस्तर पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि

किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अत्यंत आवश्यक है। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में शासन द्वारा निर्धारित राजस्व वसूली लक्ष्य की भी समीक्षा की गई। प्रभारी कलेक्टर श्री राठौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लक्ष्य पूर्ण के लिए अभी से प्रभावी रणनीति बनाकर कार्यवाही प्रारंभ करें तथा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की प्रभारी कलेक्टर ने की समीक्षा

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न

राष्ट्रबाण संवाददाता
rashtrabaan.in

प्रभारी कलेक्टर अनिल कुमार राठौर ने शुक्रवार को जिला स्वास्थ्य समिति की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जयपाल सिंह ठाकुर, सिविल सर्जन

डॉ. विनोद नावकर, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सहित सीडीपीओ एवं बीएमओ उपस्थित रहे। बैठक में विकासखंडवार गर्भवती महिलाओं के एनसी पंजीयन, स्वास्थ्य जांच तथा चिह्नित एनीमिक गर्भवती महिलाओं के उपचार की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। प्रभारी कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पात्र सभी महिलाओं का शत-प्रतिशत एनसी पंजीयन सुनिश्चित किया जाए तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक जांच समय पर कराई जाए। उन्होंने जांच रिपोर्ट के आधार पर जल्दतम महिलाओं को त्वरित उपचार एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध

कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के नियमित टीकाकरण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही टीकाकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए। एचपीवी वैक्सिनेशन अभियान की समीक्षा के दौरान उन्होंने लक्ष्य के अनुरूप शेष बालिकाओं के टीकाकरण को शीघ्र पूर्ण करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। टीबी स्क्रीनिंग की समीक्षा करते हुए प्रभारी कलेक्टर ने निष्पक्ष मित्र अभियान में जनसहभागिता बढ़ाने तथा टीबी परीक्षणों को अधिक से अधिक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

राष्ट्रबाण संवाददाता
rashtrabaan.in

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी कलेक्टर अनिल कुमार राठौर ने की। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती डेहरिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह, जनपद एवं नगरीय निकायों के अधिकारी, विभिन्न



विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत जिले में संचालित की जाने वाली व्यवस्थाओं एवं कार्ययोजनाओं की विस्तार से

संग्रहण व्यवस्था को प्रभावी रूप से संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जनजागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खुले में कचरा फेंकने एवं जलाने जैसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जाए तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित परिपत्तियों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। बैठक में कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण तथा आवश्यक अवसंरचना विकास को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती

अंजली शाह ने बैठक में आगामी वर्षों के लिए तैयारी का जिला स्तरीय बैठक संपन्न

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय बैठक संपन्न स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था के लिए दिए निर्देश